

समक्ष आदर्श कुमार गोयल और अजय कुमार मित्तल से पहले, माननीय न्यायमूर्ति।

मेसर्स शुभ टिम्ब स्टील्स लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत ए और अन्य का संघ -प्रतिवादी

2010 की सिविल रिट संख्या 11597

22 नवंबर 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226-वित्त अधिनियम, 1991- एस.एस. 65(90ए) और 65(105)(ज़ज़) - एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी व्यावसायिक संस्थाओं को वाणिज्यिक संपत्ति किराए पर देती है - व्यवसाय के लिए संपत्ति किराए पर लेकर किसी भी व्यक्ति को सेवा प्रदान करना - सेवा कर लगाना - क्या प्रविष्टि 49 सूची के अंतर्गत आती है ॥-हेल्ड, नहीं-किराये के लेन-देन में सेवा तत्व का पहलू-प्रविष्टि 92सी के अंतर्गत आने वाला एक स्वतंत्र पहलू, सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ें-पूर्वव्यापी रूप से सेवा कर लगाना-क्या विधानमंडल के पास कर लगाने को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने वाला कानून बनाने की शक्ति है-हेल्ड , हाँ-याचिका खारिज।

अभिनिर्धारित कि हम यह मानने में असमर्थ हैं कि संपत्ति के किराये की सेवा पर सेवा कर विशेष रूप से प्रविष्टि 49 सूची II द्वारा कवर किया गया है। सूची II की प्रविष्टि 49 भूमि और भवन पर कर से संबंधित है, न कि उससे संबंधित किसी गतिविधि से। संपत्ति से आय पर आयकर, भूमि और भवन सहित परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर संपत्ति कर और भूमि और भवन के उपहार पर उपहार कर को बरकरार रखा गया है। यह नहीं माना जा सकता कि संपत्ति को किराये पर देने में कोई सेवा शामिल नहीं है क्योंकि सेवा केवल संपत्ति के संबंध में हो सकती है, संपत्ति को किराये पर देने से नहीं। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति किराए पर लेना निश्चित रूप से एक सेवा है और सेवा प्राप्तकर्ता के लिए इसका मूल्य है। इसके अलावा, किराये के लेनदेन में सेवा तत्व का पहलू निश्चित रूप से सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ी जाने वाली प्रविष्टि 92C के तहत कवर किया गया एक स्वतंत्र पहलू है। किसी भी मामले में, सूची II की प्रविष्टि 49 के दायरे से बाहर होने वाली लेवी का विषय, संघ की शक्ति है। विधायिका निःसंदेह है। यह प्रश्न कि क्या आयकर और संपत्ति कर के अलावा लेवी कठोर होगी, एक बार लेवी के लिए विधायी क्षमता होने के बाद यह इस न्यायालय के लिए कोई मुद्दा नहीं

है। भले ही यह माना जाता है कि अचल संपत्ति में अधिकार के हस्तांतरण के लेनदेन में मूल्यवर्धन शामिल नहीं है, सूची II पर अतिक्रमण के अभाव में प्रावधान को शून्य नहीं माना जा सकता है।

**याचिकाकर्ता के वकील जगमोहन बंसल**

**एचपीएस घुमन, भारत संघ के वरिष्ठ स्थायी वकील।**

### निर्णय

**आदर्श कुमार गोयल, माननीय न्यायमूर्ति।**

(1) यह याचिका वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (90ए) और धारा 65 (105) (ज़ज़ज़) के प्रावधानों को संविधान के विपरीत घोषित करने की मांग करती है।

(2) याचिका में बताया गया मामला यह है कि याचिकाकर्ता एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले के परवानू में वाणिज्यिक अचल संपत्ति का मालिक है। इसने उक्त संपत्ति को व्यावसायिक संस्थाओं को किराए पर दे दिया है। इसका किराया रु. के हिसाब से मिल रहा है। अनुबंध पी-1 के अनुसार 1.75.000 प्रति माह। पट्टे का लेनदेन भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प शुल्क लगाने के अधीन है। 1899 और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 द्वारा शासित है। संपत्ति और पट्टे के विषय में मेलर राज्य विधानमंडल को सौंपे गए क्षेत्र द्वारा कवर किए जाते हैं और इस प्रकार, सामान्य विधानमंडल के दायरे से बाहर होते हैं।

(3) भारत संघ की ओर से दायर जवाब में, यह रुख अपनाया गया कि उचित किराये पर देना माल की बिक्री या संपत्ति के हस्तांतरण या परिवहन से अलग था। लेनदेन माल की बिक्री पर कर के दायरे में नहीं आता है। संपत्ति के संबंध में सेवा प्रदान करना प्रेषक कर के अंतर्गत आता था। उचित रूप से सेवा के संबंध में अन्य समान लेनदेन मंडप रखवालों (धारा 65(105)(एम) के प्रेषक थे। पंडाल शामियाना (धारा 65(105) (जेडसीडब्ल्यू)। कन्वेंशन सेवा (धारा 65 (105) (जेडसी), का अधिकार व्यवसाय सहायता सेवा के तहत व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संपत्तियों का उपयोग करें [धारा 65(105) (zzzq)]। वह लेवी प्रविष्टि 18 के तहत कवर नहीं की गई थी, यह भूमि या भवन पर कर नहीं था, बल्कि केवल सेवा तत्व पर था। कर भूमि या भवन से जुड़ा था लेकिन भूमि या भवन पर नहीं था। लेवी को प्रविष्टि 45 के तहत कवर नहीं किया गया था, जो भू-राजस्व नहीं था और न ही प्रविष्टि 49 के तहत, जिसमें प्रत्यक्ष कर पर विचार किया गया था। सेवा कर परिसर के उपयोग की अनुमति के लिए प्राप्त विचार पर था। अनुच्छेद 246 (1) के तहत। संसद अवशेष प्रविष्टि सहित सूची I के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति थी। पूर्वव्यापीता के संबंध में, यह निर्धारित किया गया है कि संशोधन स्पष्ट था। लेवी पहले से ही असंशोधित प्रावधानों के तहत प्रदान की गई थी। संशोधन का उद्देश्य दूर करना था दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय जिसके विरुद्ध अपील माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के समक्ष लंबित थी। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं होने के कारण, सेवा प्रदाताओं को कर एकत्र करना आवश्यक था, भले ही उक्त निर्णय के कारण इसे एकत्र नहीं किया जा सका हो।

(4) हमने इस याचिका में उपस्थित विद्वान वकील के साथ-साथ संबंधित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(5) विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या व्यवसाय के लिए अचल संपत्ति को किराए पर देकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सेवा प्रदान करने पर सेवा कर का आरोपण विशेष रूप से प्रविष्टि 49 सूची 11 द्वारा कवर किया गया था और सूची I की प्रविष्टि 92 सी या 97 द्वारा कवर नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह केंद्रीय विधायिका के दायरे से बाहर था, आगे प्रश्न यह है कि लेवी की वैधता 1 जून, 2007 से पूर्वव्यापी रूप से लागू की जा रही है।

(6) याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क इस प्रकार हैं: -

(1) संपत्ति को किराये पर देने की सेवा प्रदान करने पर सेवा कर लगाने का विषय प्रविष्टि 49 सूची II द्वारा कवर किया गया था, न कि सूची I की प्रविष्टि 92 सी या 97 द्वारा। किसी भी मामले में, लेवी की पूर्वव्यापीता विधायी क्षमता से परे थी। घरेलू समाधान में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले और अजय कुमार मुखर्जी बनाम बारपेक्टा के स्थानीय बोर्ड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है, (1)

(11) सेवा के माध्यम से बिना किसी मूल्यवर्धन के संपत्ति के हस्तांतरण को सेवा कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

(7) दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से प्रस्तुतीकरण यह है कि प्रविष्टि 49 सूची II का दायरा संपत्ति पर प्रत्यक्ष कर तक सीमित था, न कि संपत्ति के संबंध में किसी गतिविधि पर। किसी भी स्थिति में। प्रविष्टि 49 सूची II को सूची I की प्रविष्टि 92 सी और 97 के अधीन पढ़ा जाना था। भरोसा रखा गया है। अन्य बातों के साथ-साथ, भारत संघ में श्री हरभजन सिंह दिल्ली के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर, (2) तमिलनाडु कल्याण मंडपम एसोसिएशन। बनाम भारत संघ, (3) और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (4)। इसे जमा भी कर दिया गया

0) एआईआर 1965 एसटीसीटीएल56

(2)1971 (2)एस.सी.सी. 790

(3) 2004 (5) एस.सी.सी. 63 2

(4) (2007) 7 एस.सी.सी. 527

दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले में लेवी की वैधता का मुद्दा शामिल नहीं था और केवल संपत्ति को किराए पर देने की आय पर संपत्ति के पट्टेदारों से सेवा कर वसूलने के लिए अधिसूचना और परिपत्र की वैधता का सवाल शामिल था। उक्त निर्णय के बाद, संशोधन के माध्यम से, अचल संपत्ति

को किराए पर देने के संबंध में सेवा के बजाय, विधायिका ने प्रेषक को "अचल संपत्ति को किराए पर देने" की सुविधा प्रदान करने की अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया है। संशोधन के बाद। अचल संपत्ति का तम्बू लगाना अपने आप में एक सेवा थी करयोग्य सेवा की परिभाषा द्वारा। संपत्ति पर कर लगाने से संपत्ति के संबंध में सेवा पर कर लगाने से बाहर नहीं किया जाता है। विषय वस्तु के एक पहलू पर कर उसी विषय वस्तु के दूसरे पहलू पर कर को बाहर नहीं करता है। इसे ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित कानूनी स्थिति, प्रविष्टि 49 सूची II द्वारा कवर किए गए कर और सूची I की प्रविष्टि 92सी द्वारा कवर किए गए कर में कोई विरोधाभास नहीं था।

(8) वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सेवा कर लगाया जाता है। धारा 66 कर योग्य सेवा पर सेवा कर लगाने का प्रावधान करती है जैसा कि धारा 65 (105) के तहत परिभाषित किया गया है, धारा 65 के विभिन्न खंडों के तहत ऐसी सेवाओं की परिभाषा के साथ पढ़ा जाता है। वर्तमान मामले में, कर योग्य सेवा धारा 65(105) (zzzz) के अंतर्गत आती है जो "अचल संपत्ति को किराए पर देकर" प्रदान की गई सेवा को संदर्भित करती है। अभिव्यक्ति "अचल संपत्ति को किराये पर देना"\* को धारा 65(90ए) के तहत व्यवसाय को आगे बढ़ाने के दौरान उपयोग के लिए किराये आदि सहित परिभाषित किया गया है। सटीक परिभाषाएँ हैं: -

"65(105)'कर योग्य सेवा\* का अर्थ है प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा-

**XX XX XXX कसकसकस**

(zzzz) किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को, अचल संपत्ति को किराये पर देकर या ऐसे किराये के संबंध में किसी अन्य सेवा को, के दौरान उपयोग के लिए। व्यापार या वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए।"

स्पष्टीकरण:

**XX XX XX XX**

65(90ए). अचल संपत्ति पर टेंट लगाना' में व्यवसाय या वाणिज्य को आगे बढ़ाने के दौरान उपयोग के लिए अचल संपत्ति को किराए पर देना, किराये पर देना, पट्टे पर देना, लाइसेंस देना या इसी तरह की अन्य व्यवस्था शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है-

(i) किसी धार्मिक संस्था द्वारा अचल संपत्ति को किराये पर देना

धार्मिक संस्था; या

(ii) किसी शैक्षिक निकाय को अचल संपत्ति किराए पर देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेंटर के अलावा किसी भी विषय या क्षेत्र पर कौशल या ज्ञान या पाठ प्रदान करना:

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजन के लिए।" व्यवसाय या वाणिज्य के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग के लिए \* कारखानों, कार्यालय के रूप में अचल संपत्ति का उपयोग शामिल है। इमारतें, गोदाम, थिएटर, प्रदर्शनी हॉल और बहु-उपयोग वाली इमारतें।"

(9) वित्त अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले। 2010, 1 जून 2007 से प्रभावी। सवारी वित्त अधिनियम 2007 में शामिल "कर योग्य सेवा" की परिभाषा इस प्रकार थी: -

"65(105) 'कर योग्य सेवा\* का अर्थ है प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा-

(ए) से (ज़ज़ी) xxx

(zzzz) किसी भी व्यक्ति को, व्यवसाय या वाणिज्य के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए अचल संपत्ति को किराए पर देने के संबंध में।\*'

(10) याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क यह है कि सार और सार में, एक इमारत को किराए पर लेना सूची II की प्रविष्टि 18,45 और 49 के अंतर्गत आने वाली भूमि और इमारतों के संबंध में एक लेनदेन था, जिसके संबंध में अनुच्छेद के तहत कानून बनाने का विशेष क्षेत्राधिकार था। 246(3) राज्य 1 विधानमंडल में निहित था। लीज़िंग अधिकारों का हस्तांतरण था न कि एक सेवा और थी। इस प्रकार, सूची I की प्रविष्टि 92 सी के तहत कवर नहीं किया गया। यह स्टॉप शुल्क को आकर्षित करने वाले परिवहन की राशि है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवा प्रदाताओं की याचिका को बरकरार रखा। - होम सॉल्यूशन रिटेल इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, (5) में 18 अप्रैल, 2009 के फैसले के तहत। यह माना गया कि सेवा कर सेवा प्रदाता द्वारा मूल्यवर्धन पर लगाया गया कर था। "संबंध में" शब्दों के अनुसार, सेवा संपत्ति को किराये पर देने के संबंध में प्रदान की जानी थी और संपत्ति को अपने आप में सेवा नहीं माना जा सकता था। संपत्ति को किराये पर देने में कोई मूल्यवर्धन शामिल नहीं था। तदनुसार यह माना गया कि 22 मई की अधिसूचना। 2007 और परिपत्र दिनांक 4 जनवरी। 2008 में संपत्ति को किराये पर देने पर सेवा कर का प्रावधान करना प्रेषक कर लगाने की योजना के विपरीत था। संशोधन के माध्यम से, यहां तक कि अचल संपत्ति के किराये को भी सेवा के बजाय "कर योग्य सेवा" की परिभाषा में शामिल किया गया था

(5) (2009)22 वी.एस.टी. 508

"संपत्ति किराये पर देने के संबंध में"। संशोधन को पूर्वव्यापी बनाया गया था, जो सेवा प्रदाता पर कर लगाता था न कि सेवा प्राप्तकर्ता पर, क्योंकि सेवा प्रदाता संशोधन से पहले की अवधि के लिए सेवा प्राप्तकर्ता से प्रदान की गई सेवा की वसूली कर सकता था।

11. पहलू सिद्धांत सहित भारत के संविधान के तहत कर प्रविष्टियों की व्याख्या का मुद्दा 25 अक्टूबर, 2010 के हमारे हालिया फैसले में 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10992 (टाटा स्काई लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य) में दिया गया है। सूची II की प्रविष्टि 62 के संदर्भ में राज्य विधायिका द्वारा विधिवत मनोरंजन की वैधता के विवाद का संदर्भ, जो सूची I की प्रविष्टि 92सी के साथ टकराव में है। निम्नलिखित प्रभाव के लिए उक्त निर्णय में चर्चा से इसमें शामिल मुद्दे पर चर्चा की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा। :-

"कर प्रविष्टियों के दायरे की व्याख्या पर स्थापित कानून

9. आगे बढ़ने से पहले, डब्ल्यूसी तय कानूनी स्थिति पर गौर कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की संवैधानिक

योजना सर्वविदित है। जबकि संसद के पास सूची I के मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, राज्य विधानसभाओं के पास सूची II के मामलों के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जो कि सूची I के मामलों के संबंध में संसद की विशेष शक्ति के अधीन है। संसद और राज्य दोनों विधानमंडलों के पास सूची III के मामलों के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्ति है, जो प्रतिकूलता के मामले में प्रचलित केंद्रीय कानून के अधीन है।

10. संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत केवल तभी लागू किया जा सकता है जब संघ और राज्य सूचियों में प्रविष्टियों में असंगत विरोधाभास हो। यदि दो प्रविष्टियों को सामंजस्यपूर्ण निर्माण द्वारा या सार और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करके समेटा जा सकता है, तो संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू करने का कोई अवसर नहीं है, सूची III से संबंधित अनुच्छेद 254 के तहत प्रतिकूलता की अवधारणा सूची I में ओवरलैपिंग के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूलता से भिन्न है। और सूची 11 जिसमें विधायी क्षमता निर्धारित करने के लिए मज्जा और पदार्थ का सिद्धांत लागू किया जाता है। सूचियों में प्रविष्टियाँ कानून की शक्तियाँ नहीं बल्कि कानून के क्षेत्र हैं। विधायी क्षमता के लिए कराधान एक अलग मामला है। शिथिलता बरतने की शक्ति का अनुमान सामान्य प्रविष्टि से नहीं लगाया जा सकता। कर लगाने की शक्ति में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। अंतिम I की प्रविष्टियाँ 82 से 92C और 97 तथा सूची II की प्रविष्टियाँ 45 से 63 करों से संबंधित हैं। सूची एचएल में कर से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है।

11. प्रत्येक कर किसी वस्तु पर या कराधान की घटना पर लगाया जा सकता है। कर का विषय कराधान की घटनाओं से अलग है। संपत्ति पर कर को प्रत्यक्ष कर के रूप में वर्णित किया गया है और संपत्ति के संबंध में कर योग्य घटना पर कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में वर्णित किया गया है। यह भेद प्रभाव में अंतर पर आधारित है। किसी विशेष लेवी पर विचार करते समय, केवल शिथिलता की विषय वस्तु का वर्णन निर्णायक नहीं है।

12. कर के विषय जो एक पहलू और उद्देश्य में किसी विशेष विधायिका की शक्ति में आते हैं, वे दूसरे पहलू और उद्देश्य में दूसरे की विधायी शक्ति के अंतर्गत आ सकते हैं। इस तरह के ओवरलैपिंग को कानून में ओवरलैपिंग नहीं माना जाता है क्योंकि एक ही लेनदेन में अलग-अलग पहलुओं में दो या दो से अधिक घटनाएं शामिल हो सकती हैं। ओवरलैपिंग दस्तावेज़ पहलुओं की विशिष्टता को कम नहीं करते हैं। हालाँकि, पहलू सिद्धांत को विधायी क्षेत्रों में अतिक्रमण को उचित ठहराने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

13. इस विषय पर कुछ प्रमुख निर्णय हैं मेसर्स होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और एक अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य एआईआर 1983 एससी 1019, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, और एक अन्य वेन्सव स्टेट ऑफ एलएलपी, और अन्य (2005) 2 एससीसी 515, भारत संचार निगम लिमिटेड, और अन्य **wr.s7/.y** भारत संघ और अन्य (2006) 3 एससीसी 1 और पश्चिम बंगाल राज्य। बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2004) 10 एससीसी 201।

14. हम केसोराम इंडस्ट्रीज से अवलोकन निकाल सकते हैं:

“31. संविधान का अनुच्छेद 245 विधायी शक्ति का स्रोत है। यह इस संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रदान करता है। संसद भारत के पूरे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और किसी राज्य की विधायिका पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद और किसी राज्य की विधानमंडल के बीच विधायी क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 246 द्वारा विभाजित किया गया है। संसद के पास सातवीं अनुसूची की सूची I, जिसे "संघ सूची" कहा जाता है, में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संसद की उक्त शक्ति के अधीन, किसी भी राज्य की विधायिका को सूची III, जिसे "समवर्ती सूची" कहा जाता है, में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। उपरोक्त दोनों के अधीन, किसी भी राज्य की विधायिका के पास विशेष अधिकार हैं। सूची II, जिसे "राज्य सूची" कहा जाता है, में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 248 के तहत कानून बनाने की संसद की विशेष शक्ति समवर्ती सूची या स्लेट सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले तक विस्तारित है। किसी ऐसे कर को लागू करने का कानून बनाने की शक्ति जिसका उल्लेख समवर्ती I JST या स्लेट 1 Jsl में नहीं किया गया है, संसद में निहित है। इसे 'संसद में निहित अवशिष्ट शक्ति' कहा जाता है। इन सिद्धांतों को संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, (1983) 4 एससीसी 45 में उपलब्ध निर्णय की समीक्षा पर इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा दोहराया गया है। वे हैं :

(1) 'तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियाँ कानून की "शक्तियाँ" नहीं बल्कि कानून के "क्षेत्र" हैं। संविधान अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों की कर लगाने की शक्ति को पूर्ण रूप से अलग करता है। फैक्स करने की शक्ति में कहीं भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है और संविधान संघ और राज्यों को कराधान के स्वतंत्र स्रोत देता है।

(2) कानून के क्षेत्रों का सीमांकन किए जाने के बावजूद, संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच असहमति का सवाल केवल तभी उठ सकता है जब दोनों कानून किसी एक के संबंध में समान हों। समवर्ती सूची में शामिल मामले और सीधा टकराव नजर आ रहा है। यदि सूची के बीच ओवरलैपिंग पाए जाने के कारण कोई प्रतिकूलता है एक ओर 11 और दूसरी ओर सूची 1 और सूची एचएल, राज्य का कानून अधिकारातीत होगा और उसे संघ के कानून को रास्ता देना होगा।

(3) कराधान को प्रयोजनों के लिए एक अलग मामला माना जाता है

विधायी क्षमता. कानून और कराधान के सामान्य विषयों के बीच अंतर किया गया है। कानून के सामान्य विषयों को प्रविष्टियों के एक समूह में और कराधान की शक्ति को एक अलग समूह में निपटाया जाता है। कर लगाने की शक्ति को सहायक शक्ति के रूप में सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं निकाला जा सकता है।

(4) सूचियों में प्रविष्टियाँ केवल विधान के विषय या जेल्ड होने के कारण, उन्हें व्यापक और उदार भावना से प्रेरित एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए, न कि संकीर्ण पांडित्यपूर्ण अर्थ में। प्रविष्टियों का मसौदा तैयार करने में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों की यथासंभव व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। वी. रामास्वामी को उद्धृत करने के लिए, 'मैं' ऐसा इसलिए है क्योंकि। जे., सूचियों में विषयों

का आवंटन वैज्ञानिक या तार्किक परिभाषा के माध्यम से नहीं बल्कि व्यापक श्रेणियों की एक सरल गणना के माध्यम से होता है। प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लिखित मुख्य मामले के बारे में कानून बनाने की शक्ति में इसके विस्तार में प्रासंगिक और सहायक म्यूटर्स को छूने वाले कानून भी शामिल होंगे।

(5) जहां किसी राज्य की विधायिका की विधायी क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि यह कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है। किसी को यह प्रश्न पूछना होगा कि क्या कानून सूची 1 या III की किसी प्रविष्टि से संबंधित है। (दस्तावेजों के अनुसार, कोई और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है और संसद की विधायी क्षमता को बरकरार रखा जाना चाहिए। जहां तीन सूचियां होती हैं जिनमें बड़ी संख्या में प्रविष्टियां होती हैं, वहां उनके बीच कुछ ओवरलैपिंग होना तय है।

ऐसी स्थिति में यह निर्धारित करने के लिए कि कानून का दिया गया भाग किस प्रविष्टि से संबंधित है, मज्जा और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करना होगा। एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है, तो अन्य विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र पर किसी भी आकस्मिक खाई का कोई परिणाम नहीं होता है। अदालत को मामले के सार को देखना होगा। मज्जा और पदार्थ का सिद्धांत कभी-कभी कानून के वास्तविक चरित्र का पता लगाने के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। विधायिका द्वारा विधान को दिया गया नाम महत्वहीन है। संपूर्ण अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। आकस्मिक और सतही अतिक्रमणों की उपेक्षा की जानी चाहिए।

(6) कब्जे वाले क्षेत्र का सिद्धांत तभी लागू होता है जब संघ और राज्य सूची के बीच दोनों के लिए सामान्य क्षेत्र में टकराव होता है। वहां सार और सार के सिद्धांत को लागू किया जाना है और यदि विवादित कानून काफी हद तक उस विधायिका को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत आता है जिसने इसे अधिनियमित किया है। किसी अन्य विधायिका को सौंपे गए क्षेत्र में आकस्मिक अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तीन सूचियों को पढ़ते समय, सूची I को सूची III और II पर प्राथमिकता दी जाती है और सूची III को सूची II पर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, फिर भी, संघ सूची की प्रबलता राज्य विधानमंडल को सूची II के भीतर किसी भी मामले से निपटने से नहीं रोकेगी, हालांकि यह संयोगवश सूची I में किसी भी आइटम को प्रभावित कर सकता है।

43. रेला राम बनाम पूर्वी पंजाब प्रांत, एआईआर 1949 एफसी 81 में संघीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रांतीय कानून और संघीय कानून के प्रावधानों के बीच प्रतीत होने वाले टकराव को सुलझाने के लिए जहां तक संभव हो हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। जब तक अदालत यह राय न बना ले कि कथित आक्रमण की सीमा कितनी है

संघीय विधानमंडल के अधीन एक प्रांतीय विधानमंडल इतना महान है कि यह इस दृष्टिकोण को उचित ठहराएगा कि सार और सार में लगाया गया कर संघीय विधानमंडल के क्षेत्र के भीतर एक कर है, कर की वसूली समाप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। सर रायरुमजी जीजीभाँय मामले में निर्धारित परीक्षण। एआईआर 1941) रोम 65 को बॉम्बे प्रथम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था।



44. सहायक में. कॉमरेड I Jsl II में प्रविष्टि 49 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के उद्देश्य से शहरी भूमि फैक्स बनाम बकिंघम और ('एम ए टिक कंपनी लिमिटेड (1969) 2 एससीसी 55) का ताकि भूमि और भवनों पर कर के विवादित नियम को कवर किया जा सके। , संविधान पीठ ने दोहरे परीक्षण निर्धारित किए, अर्थात्: (i) ऐसा कर सीधे भूमि और भवनों पर लगाया जाता है, और (ii) इसका इससे एक निश्चित संबंध होता है। एक बार जब ये परीक्षण संतुष्ट हो गए, तो यह राज्य के लिए खुला था मैं कर लगाने के उद्देश्य से कर लगाने के उद्देश्य से भूमि और भवनों के वार्षिक मूल्य या पूंजीगत मूल्य को अपनाता हूं। केवल, ऐसी पद्धति अपनाए जाने के आधार पर, राज्य विधायिका पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। सूची I के Fentry 86. 87 या 88 पर अतिक्रमण किया गया है। सूची 1 में Fentry 86 एकत्रीकरण के सिद्धांत पर आगे बढ़ता है और सभी संपत्तियों के मूल्य की समग्रता पर कर लगाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भूमि और भवनों को अलग करना काफी स्वीकार्य है। सूची II में Fentry 49 के अंतर्गत कराधान। सूची 11 में Fentry 49 में प्रयुक्त भाषा के आयाम को सीमित करने का कोई कारण नहीं है। कर का उद्ग्रहण। शहरी भूमि के बाजार मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत की दर से गणना की गई, यह माना गया कि यह राज्य विधानमंडल की शक्तियों के अंतर्गत है और I Jst 1 में संविधान संख्या 86 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री पृथ्वी मामले में एक अन्य संविधान पीठ ने भी यही विचार अपनाया है। कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो म्युनिसिपैलिटी (/969) 2 एससी 'सी 283 जहां इस दलील को खारिज कर दिया गया कि लेवी भूमि और इमारतों पर एक दर नहीं थी जैसा कि उचित रूप से समझा गया था, बल्कि पूंजी मूल्य पर एक कर था।

45. आर.आर. इंजी. कंपनी बनाम जिला परिषद, बरेली, f/9W 3 SCC 330 परिस्थितियों और संपत्ति कर की एक आसानी है जो आय के आधार पर लगाया जाता है जो सहायक को अपने पेशे, व्यापार, व्यवसाय या संपत्ति से प्राप्त होता है। इस दलील को खारिज कर दिया गया कि कर आय पर एक ढीला कर था। संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित परीक्षण यह है कि परिस्थितियों पर अत्यधिक कर लगाने से आय पर कर और परिस्थितियों पर ढिलाई के बीच अंतर धुंधला हो सकता है। तब आय कर का माप या पैमाना नहीं रह जाएगा और कर की विषय-वस्तु बन जाएगी। इस संबंध में संयम स्थानीय अधिकारियों के लिए एक विवेकपूर्ण नुस्खा है जिसका पालन किया जाना चाहिए। संविधान पीठ ने कहा कि यह केवल सुविधा का मेल था कि आय को कमी का आकलन करने के लिए एक मानदंड या उपाय के रूप में अपनाया गया था और इस तरह के तंत्र का विकास कर की प्रकृति पर निर्णायक नहीं था।

50. संविधान एक जैविक जीवन दस्तावेज है। संविधान के व्याख्याकारों द्वारा समझा और व्यक्त किया गया दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति गतिशील होनी चाहिए और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। यद्यपि संविधान की मूल बातें और बुनियादी बातें अपरिवर्तित रहती हैं, संविधान के लचीले प्रावधानों की व्याख्या गतिशीलता और संघर्ष के मामले में कमजोर या अधिक जरूरतमंदों के पक्ष में की जा सकती है। केंद्र द्वारा कई कर एकत्र किए जाते हैं और समय-समय पर राज्यों को राजस्व का आवंटन किया जाता है। राजस्व के बड़े हिस्से का उपभोग करने वाले केंद्र ने स्टाल्स और वित्तीय विशेषज्ञों के हाथों अच्छी मात्रा में आलोचना की है। प्रविष्टियों की व्याख्या से संतुलन बनाया जा सकता है, या कम से कम असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, जहाँ तक यह संभव है।

राज्य की शक्तियों को जानबूझकर कम करने के किसी भी प्रयास को अदालतों द्वारा रोका जा सकता है।

"यह कहा जाए कि भारतीय संविधान में संघवाद प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि सिद्धांत का मामला है - हमारी अपनी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम और जमीनी हकीकत की पहचान।" (एससीसी पृष्ठ 217. पैरा 276)

स्कटलवाड से उद्धरण। एम.सी. टैगोर लॉ लेक्चर्स, "भारतीय संविधान के तहत संघ और स्टेट संबंध" (पूर्वी कानून 1 जून, कलकत्ता, 1974), जीवन रेड्डी, जे. ने देखा: (एससीसी पृष्ठ 217, पैरा 276)

"यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि हमारे संविधान में निश्चित रूप से राज्यों की तुलना में केंद्र के प्रति पूर्वाग्रह है। इस बात पर जोर देना भी उतना ही आवश्यक है कि अदालतों को व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा नाजुक रूप से तैयार की गई संवैधानिक योजना को परेशान न करने के लिए सावधान रहना चाहिए।"

### संक्षेप में

129. 'पिछली चर्चा से निकाले गए प्रासंगिक सिद्धांतों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

(1) सातवीं अनुसूची में सूचियों की योजना में, कानून के सामान्य विषयों और कराधान के प्रमुखों के बीच स्पष्ट अंतर मौजूद है। उनकी अलग-अलग गणना की गई है।

(2) "विनियमन और नियंत्रण" की शक्ति कराधान की शक्ति से अलग और अलग है और इसलिए कानून के प्रयोजनों के लिए दो क्षेत्र हैं। कराधान को एक विस्तारित संरचना रखकर सामान्य विधायी प्रमुख के मुख्य विषय में शामिल किया जा सकता है। , लेकिन यह सूची 1 और सूची II के बीच कराधान के लिए उपयुक्त विधायी क्षेत्र तय करने का नियम नहीं है। चूंकि कराधान के क्षेत्र सूची 1 और II में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, इसलिए कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, 'fncrc ओवरलैपिंग हो सकता है वास्तव में, लेकिन वास्तव में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन कानून में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। दो सूचियों के संदर्भ में दो करों की विषय-वस्तु अलग-अलग है। सिर्फ इसलिए कि मूल्यांकन और परिमाणीकरण के लिए अपनाई गई पद्धति या तंत्र<sup>^^</sup> समान है, दोनों करों को अतिव्यापी नहीं कहा जा सकता! - यह कर के विषय और कर के माप के बीच का अंतर है।

(3) लगाए गए कर की प्रकृति कर की माप से भिन्न होती है। जबकि कर का विषय स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित है, कर की राशि को परिमाणीकरण के उद्देश्य से कई तरीकों से मापा जा सकता है। कर के विषय को परिभाषित करना एक सरल कार्य है; कराधान का माप तैयार करना कहीं अधिक जटिल कार्य है और इसलिए विधायिका को बाद के क्षेत्र में और अधिक लचीलापन देना होगा। कर की मात्रा निर्धारित करने के लिए विधायिका द्वारा चुना गया तंत्र और तरीका कर की प्रकृति का निर्णायक नहीं है, हालांकि यह कर के सामान्य चरित्र को निर्धारित करने पर प्रकाश डालने के लिए कई कारकों में से एक प्रासंगिक कारक का गठन कर सकता है।

(5) सूची I और सूची II में प्रविष्टियों का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी टकराव से बचा जा सके। यदि कोई संघर्ष नहीं है, तो गैर-अप्रत्याशित खंड "विषय" से सहायता प्राप्त करने का अवसर

उत्पन्न नहीं होता है। यदि कोई विरोध है, तो सही तरीका यह है कि चरण दर चरण तीन प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार खोजा जाए:

एक - क्या संघर्ष और अतिव्यापन से बचने के लिए दो प्रविष्टियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना अभी भी संभव है?

दो - कानून का मर्म और सार जानने से आक्षेपित कानून किस प्रविष्टि में आता है? और

तीन - कानून के उस क्षेत्र को निर्धारित करने के बाद जिसमें विवादित कानून मथ और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करके गिरता है, क्या कानून के किसी अन्य क्षेत्र में आकस्मिक गड़बड़ी को नजरअंदाज किया जा सकता है?

(8) लेवी के चरित्र का निर्धारण करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य और कानून के आवश्यक उद्देश्य को इसके अंतिम या आकस्मिक परिणामों या परिणामों से अलग किया जाना चाहिए। मूलतः ढीली प्रकृति की और राज्य विधानमंडल की शक्ति के भीतर किसी लेवी को केवल इसलिए असंवैधानिक मानकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका वस्तु की कीमत पर प्रभाव पड़ सकता है। एक राज्य विधान, जो उपकर लगाने का प्रावधान करता है, चाहे वह राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए कर के माध्यम से हो या बदले में सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क के रूप में हो, लेकिन लेवी के विषय को विनियमित और नियंत्रित करने के किसी इरादे के बिना। , यह नहीं कहा जा सकता है कि लेवी की घटना को खरीदार या उपभोक्ता पर पारित करने की अनुमति होने के कारण केंद्र सरकार से संबंधित "विनियमन और नियंत्रण" के क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है, और इससे वस्तु या सामान की कीमत प्रभावित होती है। सूची II में प्रविष्टि 23 संघ के नियंत्रण के तहत विनियमन और विकास के संबंध में सूची I के प्रावधानों के अधीन खानों और खनिज विकास के विनियमन की बात करती है। सूची I की प्रविष्टियाँ 52 और 54 दोनों अभिव्यक्ति "संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित" द्वारा योग्य हैं। तुलनात्मक रूप से पढ़ने से पता चलता है कि संसद द्वारा घोषणा प्रविष्टि 52 में "उद्योगों के नियंत्रण" के लिए और प्रविष्टि 54 में "खानों के विनियमन या खनिज विकास के लिए" होनी चाहिए। ऐसा नियंत्रण, विनियमन या विकास "जनता के लिए समीचीन होना चाहिए" इंटरस्ट" प्रविष्टि 52 और 54 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में संघ द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानमंडलों के लिए घोषणा की विषय-वस्तु बनाने वाले पूरे क्षेत्र को कोई जादुई स्पर्श या निषेध नहीं चाहेगा। राज्य को इनकार केवल संसद द्वारा की गई घोषणा की सीमा तक ही विस्तारित होगा। प्रविष्टि '52 या 54 के संदर्भ में की गई घोषणा के बावजूद, राज्य घोषणा से छूटे हुए क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। सूची II में प्रविष्टियों के संदर्भ में कर लगाने की विधायी शक्ति पूर्ण है जब तक कि प्रविष्टि स्वयं फ़ील्ड को किसी अन्य प्रविष्टि के "अधीन" नहीं बनाती है या किसी भी सीमा के द्वारा फ़ील्ड को अधिरोपित और अनुमेय नहीं बनाती है। वस्तु के साथ राज्य द्वारा लगाया गया कर या शुल्क इसके वित्त को बढ़ाने और उचित सीमा में विषय के विनियमन, विकास या नियंत्रण पर वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अलग बात है कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर या शुल्क को स्वयं नियामक कहा जा सकता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है राजस्व का विनियमन या नियंत्रण और वृद्धि या सेवा प्रदान करना केवल गौण या आकस्मिक है।

(9) कराधान के प्रमुखों को सूची I में प्रविष्टियों 83 से 92-बी और सूची II में प्रविष्टियों 45 से 63 में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है। सूची III, समवर्ती सूची, कराधान के किसी भी मद का प्रावधान नहीं करती है। सूची I में प्रविष्टि 96, सूची II में प्रविष्टि 66 और सूची III में प्रविष्टि 47 फीस से संबंधित है। सूची I में अनुच्छेद 248(2) और प्रविष्टि 97 द्वारा वर्णित कराधान के क्षेत्र में कानून की अवशिष्ट शक्ति केवल ऐसे विषयों पर लागू की जा सकती है जो सूची आईएल की प्रविष्टि 45 से 63 में शामिल नहीं हैं। यह इस प्रकार है कि भूमि पर कर और सूची II की प्रविष्टि 49 में इमारतों पर संघ द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता है। सूची II की प्रविष्टि 50 में एक विषय, खनिज अधिकारों पर कर भी संघ द्वारा नहीं लगाया जा सकता है, हालांकि जैसा कि प्रविष्टि 50 में ही कहा गया है, संघ राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगा सकता है और ऐसी सीमाएं, यदि कोई हो, संसद द्वारा लगाई जा सकती हैं। उस सीमा तक खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा राज्यों की कानून बनाने की शक्ति सीमित हो जाएगी। खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्यों के पास है; विनियमन, विकास या नियंत्रण के हित में, जैसा भी मामला हो, ऐसी शक्ति के प्रयोग पर सीमाएं निर्धारित करने की शक्ति संघ के पास है। यह परिणाम सूची II में प्रविष्टि 50 और सूची I में प्रविष्टि 52 और 54 के सजातीय पढ़ने से प्राप्त होता है। जब तक खनिज अधिकारों पर कर या शुल्क सार और सार में रहता है, तब तक राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए कर लगाया जाता है। राज्य द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क और यह खानों और खनिज विकास के विनियमन या केंद्र सरकार द्वारा उद्योग के नियंत्रण पर प्रभाव नहीं डालता है, यह असंवैधानिक नहीं है।

पहलू सिद्धांत

15. पहलू सिद्धांत कई निर्णयों का विषय रहा है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन, ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (1989) 3 एससीसी 634 में। माना गया लेवी केंद्रीय कानून के तहत व्यय कर था, इस तर्क के संदर्भ में कि यह सूची की प्रविष्टि 62 के तहत विलासिता पर पदार्थ कर में था। द्वितीय. केंद्र सरकार का रुख यह था कि व्यय पहलू विलासिता पहलू से अलग था और व्यय पहलू को विलासिता पहलू से बाहर रखा जा सकता था। याचिका को बरकरार रखा गया. ऐसा देखा गया :-

“26 जहां भी विधायी शक्तियां संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां दो विधायी क्षेत्र स्पष्ट रूप से ओवरलैप हो सकते हैं। यह अदालतों का कर्तव्य है, भले ही यह कितना भी कठिन क्यों न हो, यह सुनिश्चित करना कि विषयों के इन वर्गों के अंतर्गत आने वाले मामलों से निपटने का अधिकार किस हद तक और किस हद तक प्रत्येक विधायिका में मौजूद है और उनके सामने आने वाले विशेष मामले में परिभाषित करना है। , 'i-संबंधित शक्तियों की सीमाएं। यह इरादा नहीं हो सकता कि ए

संघर्ष मौजूद रहना चाहिए; और, ऐसे परिणाम को रोकने के लिए दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, और एक की भाषा की व्याख्या की जानी चाहिए, और, जहां आवश्यक हो, दूसरे की भाषा में संशोधन किया जाना चाहिए।

27. प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स, एआईआर 1947 पीसी 60 में न्यायिक समिति ने सुब्रमण्यम चेट्टियार मामले 4 में सर मौरिस ग्वेयर 'सी.जे.' की निम्नलिखित टिप्पणियों को मंजूरी के साथ संदर्भित किया;

"समय-समय पर यह अवश्यभावी होता है कि कानून, हालांकि एक सूची में एक विषय से निपटने का दावा करता है, दूसरी सूची में एक विषय को भी छूता है, और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को इतनी बारीकी से जोड़ा जा सकता है कि सख्ती से अंध-पालन किया जा सकता है। मौखिक व्याख्या के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कानून अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे क्योंकि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उन्हें लागू करने वाली विधायिका ने निषिद्ध क्षेत्र में कानून बनाया है। मुझे वह नियम पसंद है जो न्यायिक समिति द्वारा विकसित किया गया है, जिसके तहत विवादित कानून की जांच उसके 'मिथ और सार', या उसकी 'वास्तविक प्रकृति और चरित्र' का पता लगाने के लिए की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मामलों के संबंध में कानून है या नहीं। इस सूची में या उस सूची में।"

28. यह शक्तियों के विभाजन के अर्थ पर निर्णय लेने के लिए "संघीय सरकार के लिए सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों से स्वतंत्र एक निष्पक्ष निकाय की भूमिका को अनिवार्य बनाता है", न्यायालय यह निकाय है।

29. वर्तमान मामले में स्थिति थोड़ी अलग तरह की है। यह याचिकाकर्ताओं के मामले का कोई हिस्सा नहीं है कि "व्यय कर" राज्यों की शक्ति के भीतर करों में से एक है या यह केंद्रीय संसद के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र है। इसके विपरीत, यह विवादित नहीं है कि एक कानून "लगाता है" व्यय कर" सूची। की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 248 के तहत केंद्रीय संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत है। लेकिन विशिष्ट तर्क यह है कि लागू कानून के तहत विशेष शुल्क। इसकी प्रकृति और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, वास्तव में "नहीं" है। व्यय कर" बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यह ऐसे कर के बारे में अर्थशास्त्रियों की धारणा के अनुरूप नहीं है। यह तर्क का एक अंग है। दूसरा यह है कि कानून वास्तव में विलासिता या विलासिता पर कर लगाने वाला है। माल की बिक्री के लिए भुगतान की गई कीमत। इसलिए, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अर्थशास्त्रियों की इस तरह के कर की अवधारणा विधायी शक्ति को योग्य बनाती है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या "व्यय" को निर्धारित किया जा सकता है। विलासिता" या वस्तुओं की खरीद पर कर कानून के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में मान्यता के अतिसंवेदनशील एक विशिष्ट पहलू के रूप में अलग-थलग और पहचाने जाने की बात स्वीकार की जाती है।

30. एलसीफ्रॉय के कनाडा की संघीय प्रणाली में विद्वान लेखक ने कनाडाई संविधान की धारा 91 और 92 यानी ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, 1867 के तहत "कानून के पहलुओं" का जिक्र करते हुए कहा है कि "सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक जिसे बहुत पसंद किया गया है" विधायी शक्ति के वितरण के संबंध में न्यायिक निर्णय यह है कि जो विषय एक पहलू में और एक उद्देश्य के लिए किसी विशेष विधायिका की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, वे दूसरे पहलू में और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी अन्य विधायी शक्ति के अंतर्गत आ सकते हैं।" विद्वान लेखक कहते हैं:

"पहलू" से कानून के उद्देश्य, उद्देश्य और दायरे को कानून बनाने में विधायक के पहलू या दृष्टिकोण को समझा जाना चाहिए कि इस शब्द का इस्तेमाल कानून बनाए गए मामले के उद्देश्य के बजाय विधायक के व्यक्तिपरक रूप से किया जाता है।"

ब्रिटिश कोलंबिया की यूनियन कोलियरी कंपनी बनाम ब्रायडेन, 1899 एसी 580 में, लॉर्ड आई लालडेन ने कहा:

"यह उल्लेखनीय है कि जिस तरह से इस बोर्ड ने धारा 91 और धारा 92 के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित किया है, यह मानते हुए कि जो विषय एक पहलू में धारा 91 के अंतर्गत आते हैं, वे दूसरे पहलू के तहत धारा 92 के अंतर्गत आ सकते हैं।"

31. वास्तव में, किसी विषय के संबंध में कानून संयोगवश किसी अन्य विषय को किसी तरह से "प्रभावित" कर सकता है; लेकिन यह बाद वाले विषय पर कानून के समान नहीं है। ओवरलैपिंग हो सकती है; लेकिन ओवरलैपिंग कानून में होनी चाहिए। एक ही लेन-देन में **iLs di (terent पहलुओं)** में दो या दो से अधिक कर योग्य घटनाएं शामिल हो सकती हैं। लेकिन यह तथ्य कि ओवरलैपिंग है, पहलुओं की विशिष्टता को कम नहीं करता है। गवर्नर-गवर्नर-इन-काउंसिल बनाम मद्रास प्रांत में लॉर्ड सिमंड्स, एआईआर 1945 पीसी 98 में उत्पाद शुल्क और माल की बिक्री पर टिलाई की अवधारणाओं के संदर्भ में कहा गया है:

"...दो कर, एक निर्माता पर उसके माल के संबंध में लगाया जाता है, दूसरा विक्रेता पर लगाया जाता है। उसकी बिक्री, जैसा कि बताया गया है, एक अर्थ में ओवरलैप हो सकती है। लेकिन कानून में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। यानी करों को अलग किया जाता है और अलग-अलग कर लगाए जाते हैं। यदि वास्तव में वे ओवरलैप होते हैं, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उत्पाद शुल्क लगाने वाले कर प्राधिकारी को उस समय उस शुल्क को लगाना सुविधाजनक लगता है जब उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु अपनी बिक्री के अवसर पर पहली बार कारखाने या कार्यशाला से निकलती है। "

32. "पहलू" सिद्धांत का उल्लेख करते हुए लास्किन के कनाडाई संवैधानिक कानून में कहा गया है:

"पहलू" सिद्धांत उन लोगों से कुछ समानता रखता है जिन्हें अभी नोट किया गया है, लेकिन, उनके विपरीत, यह इस बात से संबंधित नहीं है कि 'मामला' क्या है, बल्कि इससे संबंधित है कि यह 'अंदर क्या आता है' (पृ. 115) यह वहां लागू होता है जहां कुछ संवैधानिक तत्व जिनके बारे में जिस संयोजन से कानून का संबंध है (अर्थात्, वे इसके 'मामले' हैं), वे एक प्रकार के हैं जो विषयों के एक वर्ग के संबंध में सबसे अधिक बार पाए जाते हैं और अन्य एक प्रकार के होते हैं जो अधिकतर दूसरे के संबंध में निपटाए जाते हैं। जैसा कि चाकू ब्लेड, स्क्रूड्राइवर, फिशस्केलर, नेलफाइल इत्यादि को कॉम्पैक्ट रूप से असेंबल करने वाले पॉकेट गैजेट के मामले में होता है, इसके विवरण में हर चीज का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन इसे चिह्नित करने में इसके लिए किए जाने वाले विशेष उपयोग से यह निर्धारित होता है कि यह क्या है। (पृ. 116)

".... मैं ऑपरेटिव असंगति और 'पहलू' सिद्धांत के कुछ सहसंबंधों पर टिप्पणी करने के लिए रुकता हूं। दोनों एक कानून की समग्र प्रकृति से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से जुड़ते हैं, एक संघीय रूप से विनियमित आचरण के घटकों पर असर डालने वाले प्रांतीय उपायों पर संघीय कानून के पूर्ववर्ती प्रभाव

के संबंध में, दूसरा यह पहचानने के लिए कि पूरे 'मामले' के कौन से हिस्से इसे लाते हैं। विषयों की एक कक्षा के भीतर "(पृष्ठ 117)।

16. एक ही मामले के विभिन्न पहलुओं के उदाहरण के माध्यम से, राज्य कानून के तहत संपत्ति पर कर और केंद्रीय कानून के तहत आय पर कर का उदाहरण भी दिया गया था:

"38. वास्तव में, एक ही मामले के विभिन्न पहलुओं के उदाहरण के रूप में, विभिन्न विधायी शक्तियों के तहत कानून का विषय होने के नाते, एक पहलू में किसी व्यक्ति के कब्जे में उसके स्वयं के निवास के लिए संपत्ति के वार्षिक किराये के मूल्य का संदर्भ दिया जा सकता है। , राज्य कानून के तहत संपत्ति कर लगाने का उपाय और एक अन्य पहलू में आयकर के उद्देश्य के लिए अनुमानित या अनुमानित आय का गठन होता है।

17. ऑल-इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2007) 7 एससीसी 527 में, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स द्वारा प्रदान की गई सेवा पर सेवा कर लगाने को चुनौती दी गई थी और उस पर आपत्ति थी। प्रविष्टि 60 सूची II के आधार पर व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगार पर कर लगाने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति प्रदान की गई है। चुनौती को खारिज करते हुए, यह माना गया कि सूची II की प्रविष्टि 60 में सेवाओं पर कर शामिल नहीं था, पेशे पर ढिलाई पेशेवर प्रेषक पर कर से अलग थी। ऐसा देखा गया :

"34. जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रविष्टि 60, सूची II व्यवसायों आदि पर करों को संदर्भित करती है। यह व्यक्तिगत व्यक्ति/फर्म या कंपनी पर कर है। यह स्थिति पर कर है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार एक प्राप्त करता है अभ्यास करने के लिए सक्षम निकाय से लाइसेंस या विशेषाधिकार। उस विशेषाधिकार पर राज्य प्रविष्टि 60 के तहत कर लगाने में सक्षम है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रविष्टि 60 एक सामान्य प्रविष्टि नहीं है। इसे हर गतिविधि को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट द्वारा विचारार्थ लिया जाता है। सेवा कर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट या एक आर्किटेक्ट द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि पर एक कर है। लागत अकाउंटेंट/सीबार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट अपने ग्राहक से सलाह के लिए या खातों की ऑडिटिंग के लिए शुल्क लेता है। इसी प्रकार, एक लागत लेखाकार अपने ग्राहक से सलाह के साथ-साथ लागत निर्धारण का कार्य करने के लिए भी शुल्क लेता है। प्रत्येक लेनदेन या अनुबंध के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार पेशे आधारित सेवाएं प्रदान करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार या एक द्वारा की जाने वाली गतिविधि वास्तुकार के दो पहलू हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट के दृष्टिकोण से यह उनके प्रदर्शन और कौशल के आधार पर की जाने वाली गतिविधि है। लेकिन अपने ग्राहक के दृष्टिकोण से, चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट उसका सेवा प्रदाता है। यह "सेवाओं" पर एक कर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा की गई गतिविधि करदाता द्वारा उत्पादित बिक्री योग्य या विपणन योग्य वस्तुओं के समान है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत घरेलू उपभोग के लिए निर्धारित द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

43. जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूचियों में प्रत्येक प्रविष्टि की एक योजनाबद्ध व्याख्या की जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, संवैधानिक कानून अवधारणाओं और सिद्धांतों के बारे में है।

इनमें से कुछ सिद्धांत न्यायिक निर्णयों से विकसित हुए हैं। उक्त परीक्षण कराधान कानूनों पर भी लागू होता है। यही कारण है कि सूचियों में प्रविष्टियों को दो समूहों में विभाजित किया गया है, एक सामान्य विषयों से संबंधित है और दूसरा कराधान से संबंधित है। कराधान से संबंधित प्रविष्टियाँ सामान्य प्रविष्टियों की तुलना में भिन्न प्रविष्टियाँ हैं। यही कारण है कि संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों में प्रत्येक प्रविष्टि के दायरे को तय करने में पिथ और पदार्थ के सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है, पिथ और पदार्थ का यह सिद्धांत शब्दों से प्रवाहित होता है। अनुच्छेद 246(1), ऊपर उद्धृत, अर्थात्, "सूची टी में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में"। उक्त सिद्धांत की मूल बात यह है कि कानून को समग्र रूप से देखा जाए और यदि इसका प्रवेश के साथ कोई ठोस संबंध है, तो विषय पर कानून बनाया जा सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 246 में "के संबंध में" शब्दों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यह विधायी शक्तियों के दायरे को समझने के लिए "मिथ और पदार्थ" के सिद्धांत को लाता है।

44. अनुच्छेद 245, 246 और भाग एकसएल ए के अन्य अनुच्छेदों से वित्त अधिनियम जैसे कानून का प्रवाह कई प्रविष्टियों के आधार पर किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, हम लेवी अर्थात् सेवा कर की संवैधानिक स्थिति से चिंतित हैं। किसी लेवी का नामकरण उसके वास्तविक चरित्र और प्रकृति को तय करने के लिए निर्णायक नहीं है। किसी विशेष लेवी के वास्तविक चरित्र और प्रकृति को तय करने के लिए, विधायी क्षमता के संदर्भ में, अदालत को कानून के सार और सार पर गौर करना होगा। संसद और राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। कर कानून भाग XII और भाग XIII द्वारा शासित होते हैं। अनुच्छेद 265 अनुच्छेद 245 में आता है जब यह कहता है कि कर कानून के प्राधिकार द्वारा लगाया जाएगा। दोहराने के लिए, सातवीं अनुसूची में विभिन्न प्रविष्टियाँ दर्शाती हैं कि कर लगाने की शक्ति को विधायी क्षमता के प्रयोजन के लिए एक अलग मामला माना जाता है। यह प्रविष्टियों के दो समूहों, अर्थात् सामान्य प्रविष्टियों और कर प्रविष्टियों के बीच अंतर करने का अंतर्निहित सिद्धांत है। हमारा विचार है कि व्यवसायों, व्यापार, आजीविका आदि पर कर की तुलना में सेवाओं पर कर एक अलग विषय है। सूची 11 की प्रविष्टि 60 और सूची I की प्रविष्टियाँ 92-सी/97 विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होती हैं।

46. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक निगम में। बनाम हरियाणा का राज्य (1981) 2 एससीसी 318। अपीलकर्ता परिवहन संचालक थे। हरियाणा राज्य ने हरियाणा यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1952 के तहत यात्रियों और माल पर कर लगाया। अपीलकर्ताओं ने यात्रियों पर कर लगाने और उनके वाहनों द्वारा माल की ढुलाई के संबंध में धारा 3(3) की वैधता पर सवाल उठाया। राष्ट्रीय राजमार्ग। अपीलकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसद को सूची I की प्रविष्टि 1 से 96 में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अपनी शक्ति को सूची 1 की प्रविष्टि 97 के तहत कानून बनाने की अपनी शक्ति के साथ संयोजित करने से रोक सके। यदि ऐसा है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर ले जाए जाने वाले यात्रियों और माल पर कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद की विशेष विधायी क्षमता के भीतर थी और इसलिए, 1 लारियाना पैसंजर्स एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट, 1952 की धारा 3(3) परे थी राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता। इस तर्क को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया, जिसने यह विचार किया कि प्रविष्टि 97, सूची I का सहारा लेकर संसद से विशेष विधायी क्षमता का दावा किया जा सकता है।



विधानमंडल की स्थापना होनी चाहिए। प्रविष्टि 97 स्वयं विशिष्ट थी। उसमें, किसी मामले को उस प्रविष्टि के अंतर्गत तभी लाया जा सकता है जब वह सूची II या III में सूचीबद्ध न हो, और कर के मामले में, यदि उन सूचियों में इसका उल्लेख नहीं किया गया हो। हम उपरोक्त प्रस्ताव पर विवाद नहीं करते। वह प्रस्ताव अच्छी तरह से तय हो चुका है। यह न्यायालय इस मामले में उक्त सिद्धांत के अनुप्रयोग से चिंतित है। वर्तमान मामले में, जैसा कि यहां ऊपर कहा गया है, राज्य विधानमंडल को व्यवसायों, व्यापारों, आजीविका आदि पर कर लगाने का अधिकार है, और इसलिए, शब्द "सेवाओं" को "पेशे" शब्द के पर्याय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। प्रविष्टि 60 में। इसलिए, सेवाओं पर कर प्रविष्टि 60 के अंतर्गत नहीं आता है। सूची III कि, सेवा कर सूची 1 की प्रविष्टि 92-सी/प्रविष्टि 97 के अंतर्गत आएगा।

48. 7 वी, कल्याण मन दपम असन, बनाम भारत संघ, (2004) 5 एससीसी 632 में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना कि सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे अधिसूचित सभी सेवाओं पर भुगतान किया जाना है। भारत सरकार। आगे यह माना गया है कि उक्त कर "सेवा" पर है, न कि सेवा प्रदाता पर। पैरा 5 8 में यह देखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 246(1) के तहत, संसद के पास संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची I में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, राज्य सरकार के पास सूची II (राज्य सूची) में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। उक्त निर्णय में, यह माना गया है कि सेवा कर सूची I की प्रविष्टि 97 के तहत संसद द्वारा बनाया गया है। इसलिए, हमारे विचार में, वर्तमान मामले में मुद्दा टीएन में इस न्यायालय के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। कल्याण मंडपम. बेशक, वर्तमान मामले में, हम मंडपपाल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से चिंतित नहीं हैं, जो वह कार्य करता है जिसे संपत्ति आधारित सेवाएं कहा जाता है। इस मामले में, हम प्रदर्शन आधारित सेवाओं से चिंतित हैं। हालाँकि, दोनों श्रेणियाँ "सेवाएँ" शब्द के दायरे में आती हैं।

49. गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2005) ए एससीसी 21 ए में यह माना गया कि सेवा कर माल या यात्रियों पर कर नहीं है, बल्कि यह परिवहन पर ही था। इसलिए, यह संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 97 के तहत संसद की अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है। आगे यह माना गया कि सेवा कर यात्रियों या वस्तुओं पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि माल की ढुलाई के संबंध में सेवा की स्थिति पर लगाया जाता है और इसलिए, यह मानना संभव नहीं है कि यह अधिनियम राज्य के विशेष दायरे में है। सूची II की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत शक्तियाँ। यह माना गया कि प्रेषक कर सूची I की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत आता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम सूची II की प्रविष्टि 60 से चिंतित हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सेवा में शिथिलता प्रदर्शन आधारित सेवाओं पर ही है। यह पेशेवर सलाह, कर योजना, ऑडिटिंग, लागत निर्धारण आदि पर है। किए गए प्रत्येक कार्य पर कर देय हो जाता है। इसलिए, उपरोक्त निर्णय का कोई औचित्य नहीं है।"

(12) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, डब्ल्यूसी अब वर्तमान मामले में प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार कर सकता है।

(13) वित्त अधिनियम के माध्यम से। 1994. सेवा कर की अवधारणा पेश की गई। उक्त कमी गंतव्य आधारित उपभोग कर है जो व्यवसाय पर नहीं बल्कि उपभोक्ता पर लगाया जाता है और प्रदान की

गई सेवा पर लगाया जाता है। इस प्रकार, आईएल मूल्य वर्धित कर है। सेवाएँ संपत्ति आधारित या प्रदर्शन आधारित हो सकती हैं।

(14) ऊपर चर्चा की गई संविधान के तहत योजना के अनुसार, एक पहलू में किसी विशेष विधायिका की शक्ति में आने वाले कर का विषय दूसरे पहलू में दूसरे की विधायी शक्ति के अंतर्गत आ सकता है। ऐसी ओवरलैपिंग अपरिहार्य है। एक ही लेन-देन में अलग-अलग पहलुओं में दो या दो से अधिक घटनाएं शामिल हो सकती हैं। कानून और कराधान के सामान्य विषयों के बीच अंतर है। चे प्रविष्टियों को उदार निर्माण प्राप्त करना होगा। यदि कोई ओवरलैपिंग है, तो सार और सार का सिद्धांत लागू किया जाना है और न्यायालय को मामले के सार को देखना होगा। सूची I को सूची II पर प्राथमिकता है, हालांकि सूची I की प्रबलता स्लेट विधानमंडल को सूची 11 के तहत मामलों से निपटने से नहीं रोकती है।

(15) प्रविष्टि 49 सूची II विभिन्न निर्णयों का विषय रहा है और इसके दायरे के बारे में दी गई व्याख्या यह है कि यह सीधे भूमि और भवनों पर कर को कवर करता है। ऐसे कर के निर्धारण के लिए भूमि और भवनों के वार्षिक मूल्य या पूंजीगत मूल्य को आधार बनाया जा सकता है। संपत्ति से होने वाली आय पर प्रविष्टि 82 सूची I के तहत कर लगाया जा सकता है। संपत्ति कर भूमि और भवन के पूंजीगत मूल्य पर लगाया जा सकता है और ऐसा कर सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ी जाने वाली प्रविष्टि 86 के अंतर्गत आएगा, न कि सूची II की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत। भूमि और भवन के पूंजीगत मूल्य पर ढिलाई भूमि और भवन पर कर से भिन्न थी।

(16) एच.एस. में ढिल्लों ने, सुधीर चंद नवा बनाम वेल्थ टैक्स ऑफिसर में पहले के फैसले के उद्धरण के बाद, (6) को प्रविष्टि 86 सूची I और प्रविष्टि 49 सूची II के दायरे में उद्धृत किया था:

“कर जो प्रविष्टि 86 द्वारा लगाया जाता है; सातवीं अनुसूची की सूची I सीधे तौर पर भूमि और भवनों पर कर नहीं है। यह मूल्यांकन तिथि पर व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर लगाया जाने वाला कर है। कर निर्धारिती की संपत्ति के घटकों पर नहीं लगाया जाता है; यह कुल संपत्ति पर लगाया जाता है जो निर्धारिती के पास है, और शुद्ध संपत्ति का निर्धारण करने में न केवल संपत्ति की किसी भी वस्तु के खिलाफ विशेष रूप से लगाए गए भार, बल्कि अपने ऋणों का भुगतान करने और अपने वैध दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्धारिती की सामान्य देनदारी भी शामिल है। ध्यान में रखा जाना चाहिए... फिर से सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 49 सूची II भूमि और भवनों, या दोनों पर इकाइयों के रूप में कर लगाने पर विचार करती है। यह आम तौर पर कर के दायरे में लाई जाने वाली भूमि या इमारतों की इकाइयों में हित या स्वामित्व के विभाजन से चिंतित नहीं है। भूमि और भवनों पर कर सीधे तौर पर भूमि और भवनों पर लगाया जाता है और इसका एक निश्चित संबंध होता है। परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर का भूमि और भवनों से कोई निश्चित संबंध नहीं है जो निर्धारिती की कुल संपत्ति का एक घटक बन सकता है। प्रविष्टि 86 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून द्वारा, सूची I कर को संपत्ति के मूल्य पर लगाए जाने पर विचार किया जाता है, प्रविष्टि 49 के तहत कर लगाने के उद्देश्य से, सूची II राज्य विधानमंडल वार्षिक कर की घटनाओं का निर्धारण करने के लिए अपना सकता है। या भूमि और भवनों का पूंजीगत मूल्य। लेकिन कर देयता

निर्धारित करने के लिए भूमि और भवनों के वार्षिक या पूंजीगत मूल्य को अपनाने से, हमारे फैसले में, दो प्रविष्टियों के तहत कानून के क्षेत्र ओवरलैपिंग नहीं होंगे।"

(17) उपरोक्त के अलावा, शहरी भूमि कर के सहायक आयुक्त बनाम बकिंघम और कर्नाटक कंपनी में निम्नलिखित टिप्पणियां। लिमिटेड, (7) पर भी ध्यान दिया गया:-

दोनों प्रविष्टियों के तहत कराधान का रिक आधार काफी अलग है। जहां तक सूची I की प्रविष्टि 86 का संबंध है, कराधान का आधार संपत्ति का पूंजी मूल्य है। यह मूल्यांकन तिथि पर व्यक्तियों और कंपनियों के पूंजीगत मूल्य पर सीधे कर नहीं है। कर निर्धारितकर्ता की संपत्ति के घटकों पर कर नहीं लगाया जाता है। प्रविष्टि 86 के तहत कर एकत्रीकरण के सिद्धांत पर आगे बढ़ता है और सभी संपत्तियों के मूल्य की समग्रता पर लगाया जाता है। यह कुल परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है जो निर्धारिती के पास है और शुद्ध संपत्ति का निर्धारण करने में न केवल परिसंपत्ति की किसी भी वस्तु के खिलाफ विशेष रूप से लगाए गए ऋणभार, बल्कि अपने ऋणों का भुगतान करने और अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्धारिती की सामान्य देनदारी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। खाते में... लेकिन सूची 11 की प्रविष्टि 49, भूमि और भवनों या दोनों पर इकाइयों के रूप में कर लगाने पर विचार करती है। इसका संबंध उन भूमियों या भवनों की इकाइयों में हित या स्वामित्व के विभाजन से नहीं है, जिन्हें कर के दायरे में लाया जाता है। भूमि और भवनों पर कर, सीधे भूमि और भवनों पर लगाया जाता है और इसका एक निश्चित संबंध होता है। परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर का भूमि और भवनों से कोई निश्चित संबंध नहीं है जो निर्धारिती की कुल संपत्ति का एक घटक बन सकता है। प्रविष्टि 86, सूची 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून द्वारा, संपत्ति के मूल्य पर कर लगाए जाने पर विचार किया गया है। प्रविष्टि 49, सूची II के तहत कर लगाने के उद्देश्य से, राज्य विधानमंडल कर की घटना का निर्धारण करने के लिए भूमि और भवनों के वार्षिक या पूंजीगत मूल्य को अपना सकता है। लेकिन खननकर दायित्व के लिए भूमि और भवनों के वार्षिक या पूंजीगत मूल्य को अपनाने से दो प्रविष्टियों के तहत कानून के क्षेत्र ओवरलैपिंग नहीं होंगे। दोनों कर मूल अवधारणा में पूरी तरह से अलग हैं और अलग-अलग विषय-वस्तुओं पर आते हैं।" (जोर दिया गया)।

उपहार कर अधिकारी में निम्नलिखित टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया गया था

बनाम डी. एन. नाज़रेथ, (8)

"चूंकि राज्य सूची की प्रविष्टि 49 भूमि और भवनों के सामान्य स्वामित्व के कारण सीधे लगाए गए कर पर विचार करती है, इसलिए इसमें संसद द्वारा लगाए गए उपहार कर को शामिल नहीं किया जा सकता है।"

इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया:-

"74. प्रविष्टि 49 के तहत कर की आवश्यकताएँ सूची II को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(1) यह इकाइयों पर कर होना चाहिए, अर्थात् भूमि और भवन अलग-अलग इकाइयों के रूप में।

(2) कर समग्रता पर कर नहीं हो सकता है, यानी, यह सभी भूमि और भवनों के मूल्य पर एक समग्र कर नहीं है।

(3) कर का संबंध भवन या भूमि में हित के विभाजन से नहीं है। दूसरे शब्दों में, इससे कोई सरोकार नहीं है कि एक व्यक्ति इसका मालिक है या उस पर कब्जा करता है या दो या दो से अधिक व्यक्ति इसका मालिक हैं या उस पर कब्जा करते हैं।

(75) संक्षेप में, प्रविष्टि 49, सूची II के तहत कर, व्यक्तिगत लापरवाही नहीं है बल्कि संपत्ति पर कर है।

(18) उक्त निर्णय में संदर्भित कनाडाई संविधान के संदर्भ में व्याख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों का भी संदर्भ दिया जा सकता है: -

“डोमिनियन अधिनियम की वैधता निर्धारित करने में, पहला प्रश्न यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या अधिनियम धारा 92 में गिनाए गए विषयों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत आता है, और विशेष रूप से प्रांतों के विधानमंडलों को सौंपा गया है। यदि ऐसा होता है, तो आगे प्रश्न उठेगा, क्या अधिनियम का विषय भी धारा 91 में विषयों की गणना की गई श्रेणियों में से एक में नहीं आता है, और इसलिए अभी भी डोमिनियन संसद से संबंधित नहीं है। लेकिन यदि अधिनियम धारा 91 में विषयों की किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, तो कोई और प्रश्न नहीं रहेगा।

(19) तमिलनाडु कल्याण मंडपम एसोसिएशन में, मंडप के उपयोग पर कर की वैधता पर विचार किया गया था और दलील दी गई थी कि उक्त लेवी सूची II की प्रविष्टियों 49,54 या 60 से प्रभावित होगी, जिसे श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स में निर्णयों का हवाला देने के बाद खारिज कर दिया गया था। लिमिटेड और अन्य बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और अन्य, (9) रैला राम बनाम पूर्वी पंजाब प्रांत, (10) आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (11), निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ: -

"40. पहले पहलू के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि भूमि पर कर का गठन करने के लिए, यह सीधे भूमि पर कर होना चाहिए और भूमि से आय पर कर उक्त प्रविष्टि के दायरे में नहीं आ सकता है। इसकी पुष्टि की गई थी एससी वेन-जज बेंच द्वारा इस न्यायालय के भारत सीमेंट लिमिटेड, और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, (1990) 1 एससीसी 12 पैरा 22 इस न्यायालय के कई निर्णयों पर निर्भर करता है जिसमें एस. सी. नॉन बनाम डब्ल्यू.टी.ओ., कलकत्ता शामिल हैं। , (1969) 1 एससीआर 108; सहायक शहरी भूमि कर आयुक्त बनाम बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड (1970) 1 एससीआर 268 एट 278; दूसरा उपहार-कर अधिकारी बनाम डी. एच. नाज़रेथ, (1971) 1 एससीआर 195; यूनियन ऑफ भारत बनाम एच.एस. दिल्ली, (1971) 2 एससीसी 779 एट 792; भगवान दास जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (1981)2 एससीआर 808 और वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड, पूना कैंटोनमेंट, (1959) सप्लीमेंट 2 एससीआर 63 एट 69 इस न्यायालय के कई निर्णयों में इस प्रस्ताव का पालन किया गया है।"

(20) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स में, पेशेवरों पर कर प्रदान करने वाली सूची II की प्रविष्टि 60 से प्रभावित होने के कारण अभ्यास करने वाले पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर

सेवा कर की वैधता के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी। सेवा कर की अवधारणा पर, यह देखा गया: -

fi) "सेवा कर" का अर्थ

(22) जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रेषक कर की अवधारणा का स्रोत अर्थशास्त्र में निहित है। यह एक आर्थिक अवधारणा है। यह सेवा उद्योग के सकल घरेलू उत्पाद (9)"(1969)2एस.सी.सी. में प्रमुख योगदानकर्ता बनने के कारण विकसित हुआ है। 283

(10) एआईआर 1949 ई.सी. 81

(11) (1975)2 एस.सी.सी. 274

एक अर्थव्यवस्था की, विशेषकर ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की। वित्त अधिनियम, 1994 के अधिनियमन के साथ, केंद्र सरकार ने सेवाओं पर कर लगाने के लिए संघ सूची की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 से अपना अधिकार प्राप्त किया। संविधान (अस्सीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 268-ए की शुरुआत द्वारा कानूनी बैकअप प्रदान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सेवाओं पर कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और केंद्र सरकार और के बीच विनियोजित किया जाएगा। राज्य। इसके साथ ही, सेवा कर लगाने के लिए संघ सूची में एक नई प्रविष्टि 92-सी भी पेश की गई। जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक आर्थिक अवधारणा के रूप में, वस्तुओं की खपत और सेवाओं की खपत के बीच कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं। यह समतुल्यता के कानूनी सिद्धांत पर आधारित आर्थिक अवधारणा है जिसे अब संविधान (अस्सीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कि "सेवा कर" एक मूल्य वर्धित कर है जो बदले में एक सामान्य कर है जो वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के प्रावधान से जुड़ी सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर लागू होता है। इसके अलावा, वैट एक उपभोग कर है क्योंकि यह ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है।

सेवा कर को व्यावसायिक कर से अलग करते हुए, यह देखा गया:-

"35. प्रत्येक अनुबंध के लिए, वित्त अधिनियम, 1994 और 1998 के तहत कर लगाया जाता है। सेवा प्रदान किए बिना उस अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है जबकि प्रविष्टि 60 के तहत एक पेशेवर कर उसकी स्थिति पर एक कर है। यह लागत लेखाकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थिति पर लगने वाला कर है। जब तक व्यक्ति/फर्म इस पेशे में रहता है, उसे प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। उस कर का उन व्यावसायिक गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है जो वह अपने ग्राहक के लिए करता है। भले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पूरे लेखांकन वर्ष में कोई काम न हो, फिर भी उसे प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। जब तक वह पेशे में रहेगा तब तक उसे टैक्स चुकाना होगा। यह प्रविष्टि 60, सूची II का दायरा और दायरा है जो एक कर लगाने वाली प्रविष्टि है। इसलिए, प्रविष्टि 60 व्यवसायों पर कर पर विचार करती है। प्रविष्टि 60, सूची II "रोजगार पर कर" को संदर्भित करती है। सी. राजगोपालाचारी बनाम कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास, (12) में एंटी 82 सूची I के दायरे को प्रभावित किए बिना एंटी 62 सूची II के दायरे को प्रभावित किए बिना पेंशन पर आयकर को बरकरार रखने और वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड, (13) में निर्णयों का भी संदर्भ दिया गया

था। फिल्म के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर को सूची 11 की प्रविष्टि 62 के बाहर और इसके बजाय सूची 1 की अवशेष प्रविष्टि के अंतर्गत आने को बरकरार रखना। गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (14) के तहत परिवहन सेवाओं पर सेवा कर को बरकरार रखने का भी संदर्भ दिया गया। सूची I की अवशेष प्रविष्टि जो माल और यात्रियों पर कर से संबंधित सूची II की प्रविष्टि 56 के बाहर थी।

21) ) इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम टी.एन. राज्य में। (15), सात माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने बासी विधायिका द्वारा खनन पर रॉयल्टी पर कर की वैधता पर विचार किया। लेवी को प्रविष्टि 49 सूची II के दायरे से बाहर मानते हुए, यह देखा गया: -

22) भूमि पर सीधे कर और भूमि से होने वाली आय पर कर के बीच स्पष्ट अंतर है...

23) सहायक में। शहरी भूमि आयुक्त 'लैक्स बनाम बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड (1969)2 एससीसी 55 इस न्यायालय ने एससी नॉन मामले, एआईआर 1969 एससी 59 में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया, और माना कि सूची II की प्रविष्टि 49 एक कर तक ही सीमित थी। वह एक इकाई के रूप में सीधे भूमि पर था। दूसरे उपहार में कर अधिकारी. मैंगलोर बनाम डी.एच. नाज़रेथ, (1970) 1 एससीसी 749, यह माना गया कि भूमि के उपहार पर कर सीधे भूमि पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि केवल एक विशेष उपयोगकर्ता पर लगाया जाता है, अर्थात् उपहार के माध्यम से भूमि का हस्तांतरण। भारत संघ बनाम एच.एस. में दिल्ली, (1971) 2 एससीसी 779 इस न्यायालय ने एस.सी. नॉन मामले, एआईआरआई 969 एससी 59 के साथ-साथ नाज़रेथ मामले (1970) 1 एससीसी 749 में निर्धारित सिद्धांत को मंजूरी दे दी। भगवान दास जैन वेनियूनियन ऑफ इंडिया (1981) 2 एससीसी 135 में यह न्यायालय ने गृह संपत्ति से होने वाली आय पर लेवी, जो आयकर होगी, और गृह संपत्ति पर लेवी, जो आयकर होगी, के बीच अंतर किया।

(12) एआईआर 1964 एस.सी. 1172

(13) एआईआर 1959 एस.सी. 582

(14) (2005)4 एस.सी.सी. 214

(15) (1990) 1 एस.सी.सी. 12

प्रविष्टि 49 सूची आईएल का संदर्भ लें, इसलिए, श्री कृष्णमूर्ति अय्यर की अधीनता को स्वीकार करना संभव नहीं है और रॉयली पर उपकर को संभवतः कर या भूमि पर लगान नहीं कहा जा सकता है। श्री नरीमन सही कह रहे हैं कि रॉयल्टी जो अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ी है, उसे एक इकाई के रूप में सीधे भूमि पर कर नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में, विभिन्न प्रकार के करों में किए गए भेदभाव का संदर्भ दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए, पेशेवर कर और मनोरंजन कर। वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड, पूना कैंटोनमेंट, एआईआर 1959 एससी 582 मामले में, यह माना गया कि मनोरंजन कर इस बात पर निर्भर करता है कि सिनेमा घर में कोई शो होगा या नहीं। अगर कोई शो नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है। यह पेशे या व्यवसाय पर कर नहीं हो सकता। व्यावसायिक कर किसी के पेशे के अभ्यास पर निर्भर नहीं करता है बल्कि इसका संबंध केवल अभ्यास करने के अधिकार से होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा मामले में भी कोई कर नहीं लगाया जा सकता है या यदि

कोई खनन गतिविधियां नहीं की जाती हैं तो विवादित अधिनियम के तहत कर लगाया जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह एक इकाई के रूप में भूमि से संबंधित नहीं है जो सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत भूमि के मूल्यांकन की एकमात्र विधि है, बल्कि निकाले गए खनिजों से संबंधित है। निकाले गए खनिजों के एक अनुपात पर रॉयल्टी देय होती है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिनियम उस आधार के रूप में डेड रेंट का उपयोग नहीं करता है जिसके आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जाना है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विवादित कानून अपने सार और सार में रॉयल्टी पर कर है, न कि भूमि पर कर।"

(22) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि संपत्ति के किराये की सेवा पर सेवा कर विशेष रूप से प्रविष्टि 49 सूची II के अंतर्गत आता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है। सूची II की प्रविष्टि 49 भूमि और भवन पर कर से संबंधित है, न कि उससे संबंधित किसी गतिविधि से। संपत्ति से आय पर आयकर, भूमि और भवन सहित परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर संपत्ति कर और भूमि और भवन के उपहार पर उपहार कर को बरकरार रखा गया है। यह नहीं माना जा सकता कि संपत्ति को किराये पर देने में कोई सेवा शामिल नहीं है क्योंकि सेवा केवल संपत्ति के संबंध में हो सकती है, संपत्ति को किराये पर देने से नहीं। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति किराए पर लेना निश्चित रूप से एक सेवा है और सेवा प्राप्तकर्ता के लिए इसका मूल्य है। इसके अलावा, लेन-देन में सेवा तत्व का पहलू निश्चित रूप से सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ी जाने वाली प्रविष्टि 92C के तहत कवर किया गया एक स्वतंत्र पहलू है। किसी भी मामले में, सूची II की प्रविष्टि 49 के दायरे से बाहर होने वाली लेवी का विषय, संघ की शक्ति है। विधायिका निःसंदेह है। यह प्रश्न कि क्या आयकर और संपत्ति कर के अलावा लेवी कठोर होगी, एक बार लेवी के लिए विधायी क्षमता होने के बाद यह इस न्यायालय के लिए कोई मुद्दा नहीं है। भले ही यह माना जाता है कि अचल संपत्ति में अधिकार के हस्तांतरण के लेनदेन में मूल्यवर्धन शामिल नहीं है, सूची आईएल पर अतिक्रमण के अभाव में प्रावधान को शून्य नहीं माना जा सकता है।

(23) अब हम पूर्वव्यापीता के पहलू पर आते हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सक्षम विधायिका हमेशा किसी कानून को पूर्वव्यापी रूप से स्पष्ट या मान्य कर सकती है। इसे कठोर या मनमाना नहीं माना जा सकता। कानून को मान्य करने का उद्देश्य वाक्यांशविज्ञान या कमी में दोष को सुधारना और उस उद्देश्य को लागू करना और कार्यान्वित करना है जिसके लिए पहले कानून बनाया गया था।

(24) शिवदत्त राय फतेहचंद बनाम भारत संघ, (16) मामले में ऐसा देखा गया

"32. विचार करने का अगला बिंदु यह है कि क्या पूर्वव्यापी प्रभाव से जुर्माना लगाना और वसूलना याचिकाकर्ताओं के संपत्ति के मालिक होने और अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत गारंटीकृत व्यवसाय पर छूट के मौलिक अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध लगाने के समान है। और (जी) संविधान के हमने पहले ही ऊपर उन परिस्थितियों का संकेत दिया है जिनके तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से जुर्माना लगाना और जुर्माना लगाने और उसकी वसूली से संबंधित सभी कार्यवाहियों को मान्य करना आवश्यक हो गया। कर या शुल्क लगाने को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने वाला कानून बनाने की विधायिका की शक्ति के दायरे पर इस अदालत ने छोटाभाई जकटाभाई पटेल कंपनी बनाम भारत संघ, एआईआर 1962 एससी 1006 मामले में विचार किया था। अदालत ने माना कि संसद अपने दायरे में काम

करती है। विधायी क्षेत्र के पास शक्ति थी और वह कानून द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत संभावित और पूर्वव्यापी दोनों तरह से उत्पाद शुल्क लगा सकता था, यहां तक कि जहां यह स्थापित किया गया था कि कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने के कारण, निर्धारित पारित करने में असमर्थ थे। खरीदारों को उत्पाद शुल्क पर कुछ अमेरिकी निर्णयों पर विचार करते हुए, अय्यंगार, जे. ने एससीआर पी 37 में इस प्रकार अवलोकन किया:

"इस प्रकार यह देखा जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तहत भी पूर्वव्यापी कर की असंवैधानिकता 5वें संशोधन की अस्पष्ट रूपरेखा पर आधारित है।" जबकि भारतीय संविधान के तहत किसी संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन किस आधार पर किया जाता है, इसका परीक्षण उचित प्रक्रिया के लचीले नियम द्वारा नहीं बल्कि अनुच्छेद 19(5) में निर्धारित अधिक सटीक मानदंडों पर किया जाना है, केवल पूर्वव्यापीता लागू करने में कर अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के तहत संपत्ति रखने के अधिकार का उल्लंघन करने या अनुच्छेद 31 (1) के तहत संपत्ति के व्यक्ति को वंचित करने के आधार पर कानून को असंवैधानिक नहीं बना सकता है। यदि एक ओर, विचाराधीन कर अधिनियम संघ या राज्य की विधायी क्षमता से परे था, तो आवश्यक रूप से अलग-अलग विचार उत्पन्न होते हैं। इस तरह का अनधिकृत अधिरोपण निस्संदेह संपत्ति रखने के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध नहीं होगा, इसके अलावा व्यवसाय चलाने पर एक अनुचित प्रतिबंध होगा, यदि प्रश्न में कर वह है जो इस व्यावसायिक गतिविधि के संबंध में किसी व्यक्ति पर लगाया गया है।

(25) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (17) में, यह देखा गया: -

"17. पुनः बिंदु संख्या 5: इस बिंदु पर तर्क यह है कि बिक्री कर उपभोक्ता पर एक अप्रत्यक्ष कर है। विचार यह है कि विक्रेता इसे अपने क्रेता को देगा और उनसे इसे एकत्र करेगा। यदि यह बिक्री कर की प्रकृति है, तो, विद्वान अटॉर्नी जनरल का आग्रह है, इसे बिक्री लेनदेन के समापन के बाद विक्रेता से खरीदार को शीर्षक पारित करके पूर्वव्यापी रूप से नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उस स्तर पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्रेता को दे दिया गया। उनके अनुसार विक्रेता बिक्री के अवसर पर क्रेता से बिक्री कर वसूल करता है। एक बार जब वह समय बीत जाता है, तो विक्रेता क्रेता से इसकी वसूली का मौका खो देता है और यदि इसे क्रेता से वसूल नहीं किया जा सकता है, तो इसे बिक्री कर नहीं कहा जा सकता है। हमारे निर्णय में यह तर्क सही नहीं है। अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से और एक आर्थिक सिद्धांत के रूप में, बिक्री कर उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष कर हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। 1947 अधिनियम के तहत, जहां तक राज्य का संबंध है, बिक्री कर का भुगतान करने की प्राथमिक देनदारी (17) एआईआर 1958 एस.सी. 452 विक्रेता पर है। वास्तव में 1947 के अधिनियम में संशोधन से पहले विक्रेताओं के पास क्रेता से बिक्री कर वसूल करने का कोई अधिकार नहीं था। विक्रेता निःसंदेह कीमत इतनी बढ़ा सकता था कि उसमें बिक्री कर भी शामिल हो, जिसका उसे भुगतान करना होगा, लेकिन उसे - जैसे किसी भी बिक्री कर का एहसास नहीं हो सका। ऐसे क्रेता से वह परिस्थिति विक्रेता पर लगाए गए बिक्री कर को माल के एकमात्र बिक्री कर से कम नहीं रोक सकती थी। यह परिस्थिति कि 1947 के अधिनियम ने, संशोधन के बाद, विक्रेता को, जो एक पंजीकृत डीलर था, क्रेता से कर के रूप में बिक्री कर वसूलने के लिए दंडित किया, बिक्री कर का भुगतान करने के लिए विक्रेता की प्राथमिक देनदारी को समाप्त नहीं करता है। 'इलिस को इस तथ्य



से और भी स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकृत डीलर को, यदि वह चाहे या चाहे तो, क्रेता से कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है और कभी-कभी अन्य पंजीकृत डीलरों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण उसे अपना माल बेचना लाभदायक हो सकता है। बिक्री कर का त्याग करके भी उसने अपने पुराने ग्राहकों को बरकरार रखा। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बिक्री कर को क्रेताओं पर डालने की आवश्यकता नहीं है और यह तथ्य कर की वास्तविक प्रकृति को नहीं बदलता है, जो कानून के स्पष्ट प्रावधानों द्वारा विक्रेता पर डाला जाता है। खरीदार पर सहमत बिक्री मूल्य के अतिरिक्त बिक्री कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है, जब तक कि अनुबंध में विशेष रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो। लव बनाम नॉर्मन राइट (बिल्डर्स) लिमिटेड एलआर (1944) 1 केबी 484 देखें। यदि यह बिक्री कर का सच्चा दृष्टिकोण है तो अपने स्वयं के विधायी क्षेत्र के भीतर कार्य करने वाले बिहार विधानमंडल के पास एक संप्रभु विधायिका की शक्तियां थीं और वह संभावित रूप से अपना कानून बना सकता था। साथ ही पूर्वव्यापी दृष्टि से भी हमें नहीं लगता कि इस विवाद में कोई दम है।"

(26) उपरोक्त के मददेनजर, हमें 1 जून, 2007 से संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव देने को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है, जिस तारीख को शुरू में लेवी प्रदान की गई थी।

(27) तदनुसार, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज कर दिया गया।

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

*सचिन कुमार सिंह  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
(Trainee Judicial Officer)  
नूँह, हरियाणा*